an>

Tilte: Need to take steps for expediting setting up of proposed electric rail engine factory at Madhepura, Bihar.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : मैं अपने संसदीय क्षेत्र मधेपुरा (बिहार) में रेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित रेल विद्युत इंजन कारखाने की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं।

कई साल पहले रेलवे द्वारा मधेपुरा में रेल विद्युत इंजन निर्माण कारखाना खोलने हेतु अनुमोदन किया गया था। तत्कालीन रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी के द्वारा इसका शिलान्यास भी किया गया लेकिन उसके बाद से अभी तक इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। इस संबंध में मैं दिनांक 08.04.2015 को दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान के भागलपुर संस्करण में छपी खबर का जिक्र करना चाहता हूँ जो वर्तमान स्थिति का वर्णन करती है। इतने साल बीतने के बाद भी रेलवे अधिकारियों की कार्यशैली के कारण भू-अर्जन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है। इसका मुख्य कारण यहाँ के किसानों का रेलवे के द्वारा शोषण है। रेलवे के द्वारा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा पुराने दर पर दिया जा रहा है एवं किसान पुरानी दर पर मुआवजा लेने से मना कर रहे हैं। भारत सरकार नया भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाकर किसान के हित की बात कर रही है जबकि धरातल पर स्थिति कुछ और बखान कर रही है। इस खींचातानी में मधेपुरा में रेल विद्युत इंजन कारखाना की स्थिति पूर्व की भाँति जस-की-तस बनी हुई है जिससे भारत सरकार को आर्थिक क्षति के साथ-साथ औद्योगिक विकास भी रूका पड़ा है।

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि मधेपुरा के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए किसानों को नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा प्रदान कर इस गतिरोध को दूर कर किसान हितैषी बनते हुए अविलंब रेल विद्युत इंजन कारखाना चालू करवाने की कृपा की जाए।